



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 8, 1940
No. 257] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/SHRAVANA 8, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018
अंतिम जांच परिणाम

विषय:—यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सोडियम नाइट्राइट" के आयातों से संबंधित मध्यावधिक समीक्षा शुल्क जांच।

सं. 7/12/2017-डीजीएडी.—यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाठित वस्तुओं की पहचान, आकलन और पाठित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

मूल जांच

- जबकि अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ और ताइवान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे यहाँ आगे संबंद्ध सामान अथवा विचाराधीन उत्पाद अथवा पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहाँ आगे प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा 02 नवंबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 54/1/2001-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम 01 फरवरी, 2002 को अधिसूचित किए गए थे और अनंतिम शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा 28 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 34/2002-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे। प्राधिकारी ने संबंद्ध सामानों के संबंद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए 28 अक्टूबर, 2002 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। संबंद्ध

देशों से आयातित संबंद्ध सामानों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा 29 नवंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 132/2002-सीमा शुल्क द्वारा लगाए गए थे।

प्रथम निर्णयिक समीक्षा

2. उसके बाद प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ (जिसे यहां आगे "संबंद्ध देश" भी कहा गया है) से आयातों के संबंध में 06 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/6/2005-डीजीएडी द्वारा निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने 03 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/6/2005-डीजीएडी द्वारा संबंद्ध देश से संबंद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-सीमा शुल्क द्वारा संबंद्ध देश से संबंद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया।

द्वितीय निर्णयिक समीक्षा

3. उसके बाद प्राधिकारी ने 23 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी द्वारा द्वितीय निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने 12 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी द्वारा संबंद्ध देश से संबंद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने 08 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या 37/2014-सीमा शुल्क द्वारा संबंद्ध देश से संबंद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया।

वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच

4. मैसर्स दीपक नाइट्रोइट लि. ने सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अनुसार संबंद्ध देश से संबंद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक का समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में बड़ा अनुपात है। आवेदक ने दावा किया है कि जो परिस्थितियां पूर्व जांच की जांचावधि के दौरान विद्यमान थीं, उनमें काफी परिवर्तन आ गया है जिससे ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अब प्रभावी नहीं है और यह कि लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
5. आवेदक ने दावा किया है कि मौजूदा उपाय पाटन का सामना करने के लिए अपर्याप्त हैं जिससे क्षति हो रही है जिसके परिणामस्वरूप पाटित कीमतों पर आयातों की भारी मात्रा लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत में आने का दावा किया गया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के स्तरों पर भी संबंद्ध आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है और यह कि वर्तमान क्षति मार्जिन लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क से काफी अधिक है।
6. तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 11 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/12/2017-डीजीएडी द्वारा मध्यावधि समीक्षा शुरू की।

प्रक्रिया

7. संबंद्ध जांच के संबंध में नीचे निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है:
8. आवेदन पत्र की प्राथमिक जांच में कुछ कमियां सामने आई हैं जिनको बाद में याचिकाकर्ता द्वारा ठीक कर लिया गया था। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार, जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में स्थित संबंद्ध देश के दूतावासों की अधिसूचित किया। आरंभिक याचिका जांच की अवधि के रूप में जुलाई, 2016 से जून, 2017 को मानते हुए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर मामले की शुरूआत की गई थी। तथापि, चूंकि आवेदन पत्र में प्रस्तुत आंकड़े एक जांच के प्रयोजन के लिए हाल के नहीं थे, अतः अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017 तक की अवधि को जांच करने के लिए जांच की अवधि के रूप में लिया गया था। याचिकाकर्ता ने तदनुसार आंकड़ों को अद्यतन किया।
9. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और उद्योग एसोसिएशनों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक नोटिस की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने विचार देने का अवसर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर उत्तर दें।

10. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात निर्यातिकों और संबंद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र की एक प्रति, जहां भी अनुरोध किया गया था, अन्य हितवद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।
11. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना मंगाने के लिए संबंद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को प्रश्नावली भेजी:
- क. बीएएसएफ अक्तीगेसेल्सचाफ्ट, जर्मनी
 - ख. टेरा नाइट्रोजन (यूके) लि., यूके
12. संबंद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातिक ने निर्यातिक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए। तथापि, यूरोपीय आयोग ने याचिका पर तथा संबंद्ध जांच की शुरूआत पर कई आपत्तियां उठाई हैं।
13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना मंगाने के लिए भारत में संबंद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:
- क. मैसर्स अहमदाबाद केमिकल्स
 - ख. मैसर्स एसियाटिक इंडस्ट्रीज
 - ग. मैसर्स एरीज डाइकेम इंड.
 - घ. मैसर्स बकुल एरोमेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
 - ड. मैसर्स बी. आई. मेहता
 - च. मैसर्स काफिल प्रा. लि.
 - छ. मैसर्स डिनटेक्स डाइकेम लिमिटेड
 - ज. मैसर्स डायनमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - झ. मैसर्स एंजेलकेम (आई) प्रा. लि.
 - ञ. मैसर्स फार्मसन फार्मास्युटिकल्स
 - ट. मैसर्स इंडोकोल केम लि.
 - ठ. मैसर्स आइसलैंड वीरकेमी
 - ड. मैसर्स जानसन्स लिमिटेड
 - ढ. मैसर्स केटल केम प्रा. लि.
 - ण. मैसर्स मैट्रो केम इंडस्ट्रीज
 - त. मैसर्स मनीष केमिकल्स
 - थ. मैसर्स पारसीन केमिकल्स लिमिटेड
 - द. मैसर्स प्रबावा एक्सपोट्स
 - ध. मैसर्स रवि डाइवियर कं. लि.
 - न. मैसर्स रोहा डाइकेम
 - प. मैसर्स सवाकाशी डेम – ओ – फैब
 - फ. मैसर्स एसयू – वी केमिकल्स लि.
 - ब. मैसर्स सुवेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

14. जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में उपर्युक्त किसी भी आयातक, प्रयोक्ता और एसोसिएशन ने उत्तर नहीं दिया और प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए।
 15. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
 16. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
 17. इसके अतिरिक्त, आवश्यक समझी गई सीमा तक याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मांगी गई थी।
 18. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
 19. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी विक्री करने की लागत पर आधारित धृति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) इस तरह से निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
 20. यह जांच अक्टूबर, 2016 से शुरू करके सितंबर, 2017 (12 माह) (जिसे यहां आगे जांच की अवधि अथवा पीओआई कहा गया है) की अवधि के लिए की गई थी। धृति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल है।
 21. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांछियकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे दें और वे प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा धृति विश्लेषण के परिकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का प्रयोग किया है।
 22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 10 अप्रैल, 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तथापि, घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया।
 23. प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को इस प्रकटन विवरण में हल कर लिया गया है।
 24. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी को वर्तमान जांच के दौरान उत्तर नहीं दिया है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी रिकार्ड की है।
 25. इस प्रकटन विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
 26. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रूप में परिवर्तन के लिए जांच की अवधि के लिए मानी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 66.70 रूपये है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
- ग.1 घरेलू उद्योग के विचार**
27. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. लागू पाटनरोधी शुल्क की वृद्धि के लिए अनुरोध की जांच हेतु मध्यावधि समीक्षा जांच होने के नाते, इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पूर्व जांचों में परिभाषित की तरह ही है।

- ii. पूर्व जांचों में शामिल और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद उसके सभी स्वरूपों में "सोडियम नाइट्राइट" है। सोडियम नाइट्राइट एक इन-ऑर्गेनिक रसायन है और ऑक्सीडाइजिंग तथा न्यूनीकरण कारक है। यह सफेद क्रिस्टलीन चूर्ण है जिसका प्रयोग प्रायः फार्मास्युटिकल उद्योग, डाई उद्योग, लुब्रीकेंट, निर्माण रसायन, रबड ब्लोइंग एजेंट, ताप अंतरण साल्ट, मीट प्रोसेसिंग टेक्स्टाइल आदि में किया जाता है। संबंध सामानों का उत्पादन उत्प्रेरकों की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड अथवा अमोनिया से प्राप्त नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करके किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को उसके बाद सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा/सोडा राख में मिलाया जाता है। यह उत्पाद गंधहीन और पानी में घुलनशील होता है।
- iii. सोडियम नाइट्राइट सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप शीर्ष 28.34.10 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत आता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह वाध्यकारी नहीं है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबंध सामानों और भारत में आयातित संबंध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और भारत में आयातित सोडियम नाइट्राइट भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबंध क्षेत्र से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।
- v. अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबंध क्षेत्र से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।

ग.2 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. किसी भी नियांतक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है और वर्तमान जांच के तहत विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो उत्पाद का क्षेत्र है जिसके विरुद्ध पाठनरोधी शुल्क वर्तमान में लागू है।
30. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों में सोडियम नाइट्राइट है क्योंकि वित्तीय निर्णायिक समीक्षा जांच सहित यह पूर्व की जांचों में भी था।
31. सोडियम नाइट्राइट एक इन-ऑर्गेनिक रसायन है और ऑक्सीडाइजिंग तथा न्यूनीकरण कारक है। यह सफेद क्रिस्टलीन चूर्ण है जिसका प्रयोग प्रायः फार्मास्युटिकल उद्योग, डाई उद्योग, लुब्रीकेंट, निर्माण रसायन, रबड ब्लोइंग एजेंट, ताप अंतरण साल्ट, मीट प्रोसेसिंग टेक्स्टाइल आदि में किया जाता है। संबंध सामानों का उत्पादन उत्प्रेरकों की मौजूदगी में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड अथवा अमोनिया से प्राप्त नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करके किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को उसके बाद सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा/सोडा राख में मिलाया जाता है। यह उत्पाद गंधहीन और पानी में घुलनशील होता है।
32. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 28 के सीमा शुल्क शीर्ष 28.34.10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह वाध्यकारी नहीं है।
33. समान वस्तुओं के संबंध में पाठनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:
- "ऐसी वस्तु जो भारत में पाठित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं।"

34. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबंद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग तथा सामानों की उत्पाद विशिष्टि जैसे विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। विनिर्माण प्रक्रिया और प्रतिस्थापनीयता में समानता के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबंद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार "विचाराधीन उत्पाद" की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग ने, घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक नियमावली के नियम 2(ग) में परिभाषित किए गए अनुसार हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि वह भारत में समान वस्तु का उत्पादक है। संगत निर्णयक समीक्षा जांचों में दीपक नाइट्राइट लि. याचिकाकर्ता था और उसे प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के रूप में पात्र पाया गया था क्योंकि उसका भारत में "समान वस्तु" के उत्पादन में प्रमुख अनुपात था।
- मैसर्स दीपक नाइट्राइट लि. ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए समीक्षा हेतु आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता के अलावा, देश में सोडियम नाइट्राइट के तीन अन्य उत्पादक हैं, यथा – पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लि., नेशनल फर्टिलाइजर लि. और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि।। तथापि, आवेदक भारत में संबंद्ध सामानों का एक प्रमुख उत्पादक बना हुआ है और जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन में उसका 92.26 प्रतिशत हिस्सा है तथा इसीलिए घरेलू उद्योग बना हुआ है।
- याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबंद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और साथ ही वह यूरोपीय संघ में संबंद्ध सामानों के किसी नियातिक अथवा उत्पादक अथवा नियम 2(ख) के अभिप्राय से भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
- अतः इस समीक्षा के लिए आवेदक आधार की आवश्यकताएं पूरी करता है तथा पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग बना हुआ है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. किसी भी नियातिक, आयातक, उपभोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पारित वस्तु के नियातिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

38. यह आवेदन पत्र मैसर्स दीपक नाइट्राइट लि. द्वारा दायर किया गया था और इसका समर्थन पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लि. (पीसीपीएल) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफएल) ने किया था। इसके अतिरिक्त, आवेदक और समर्थक के अलावा, संबंद्ध सामानों का एक अन्य उत्पादक अर्थात् नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. है।

39. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को यह जांच करने की अपेक्षा है कि क्या (क) आवेदन पत्र का पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक

उत्पादन है; और (ब) आवेदन पत्र का समर्थन उन घरेलू उत्पादकों ने किया है जिनका सामूहिक उत्पादन पूरी तरह से समर्थन करने वाले अथवा आवेदन का विरोध करने वाले घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में उत्पादन अकेले 92.11 प्रतिशत है और पीसीपीएल और आरसीएफएल की सहायता से कुल भारतीय उत्पादन का 96.10 प्रतिशत उत्पादन है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान संबंद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह संबंद्ध देश में संबंद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

भारतीय उत्पादन का विवरण

विवरण	यूओएम	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
याचिकाकर्ता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	121	122	129
समर्थक का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
पंजाब केमिकल्स	मी. टन	***	***	***	***
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि.	मी. टन	***	***	***	***
समर्थक का उत्पादन	सूचकांक	100	32	29	61
समर्थक सहित याचिकाकर्ता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	114	114	123
अन्य भारतीय उत्पादक (एनएफएल)	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	121	122	129
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	51,922	59,088	59,334	64,143
	सूचकांक	100	114	114	124
Share in %					
याचिकाकर्ता का हिस्सा	%	***	***	***	***
समर्थक का हिस्सा	%	***	***	***	***
पंजाब केमिकल्स	%	***	***	***	***
राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि.	%	***	***	***	***
समर्थक सहित याचिकाकर्ता	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादन	%	100.00	100.00	100.00	100.00

40. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ब) तथा नियम 5(3) के तहत घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

41. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. इस संबंध में पर्यास अगोपनीय सूचना सही कारणों सहित दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई परिपाटी निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुरूप है।
- ii. संबंध मामले में 11 दिसंबर, 2017 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना संख्या फा. सं. 7/12/2017-डीजीएडी द्वारा परिवर्तित जांच की अवधि के उत्तर में याचिकाकर्ता ने 20 जनवरी, 2018 को अद्यतन अनुबंध और क्षति मार्जिन के संबंध में संगत सूचना दायर की थी तथा कीमत कटौती भी रिकार्ड में ली गई है।
- iii. याचिकाकर्ता ने याचिका में और अद्यतन अनुबंधों, दोनों में बिक्री कीमत की सूचीबद्ध सूचना प्रदान की है। वास्तविक आंकड़े व्यापार संवेदनशील सूचना हैं और अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं किए जा सकते।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

42. पारदर्शिता और गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय आयोग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. याचिका के अगोपनीय रूपांतर में दी गई सूचना पाटन मार्जिन और कटौती के परिकलनों को समझने और अपनी रक्षा के अधिकार के पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह पर्यास नहीं है।
- ii. क्षति मार्जिन और कीमत कटौती के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है क्योंकि संगत अनुबंध याचिका के अगोपनीय रूपांतर में गायब है।
- iii. याचिका में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं है। यहां तक कि सूचीरेंज के रूप में भी नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

44. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्यासिता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्यास अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

45. यह नोट किया जाता है कि जांच को सुकर बनाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना को प्रकट करना उचित नहीं होगा। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से संबंधित गोपनीय सूचना को प्रकट करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उससे घरेलू एवं विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों को अनुचित लाभ मिलेगा।

च. विविध मुद्दे

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

46. घरेलू उद्योग ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. किसी भी यूरोपीय नियर्तिक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, प्राधिकारी संबंध उत्पादकों और नियर्तिकों को असहयोगी मान सकते हैं और नियम 6(8) के अनुसार मामले में निर्णय ले सकते हैं तथा उसमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
- ii. उत्पादकों को अच्छी तरह मालूम है कि उनके आंकड़ों के अनुसार वास्तविक पाटन मार्जिन याचिकार्ता द्वारा दावा किए गए "बहुत कम" पाटन मार्जिन से वास्तविक रूप से अधिक है और वह प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- iii. यूरोपीय दूतावास ने सार्वजनिक सुनवाई से पूर्व कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की थीं जिन्हें विधिवत दायर किया गया है। चूंकि, न तो दूतावास और न ही कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उपस्थित थे, अतः प्राधिकारी को उनके द्वारा दायर किसी लिखित अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- iv. याचिकार्ता का अनुरोध है कि आवंटन तथा खर्चों के भाग के लिए याचिकार्ता द्वारा अपनाया गया सिद्धांत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे स्व-विवेक से संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। खर्चों के भाग के लिए याचिकार्ता द्वारा अपनाया गया सिद्धांत रिकार्ड में रख दिया गया है। आवेदक वर्तमान मामले में अपनाए गए सिद्धांत को अपनाकर लागत संबंधी सूचना निरंतर प्रदान करता रहा है। संबंधित उत्पाद के संबंध में कई मामले हुए हैं जिनमें प्राधिकारी ने कंपनी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तथापि, विगत कुछ मामलों में प्राधिकारी बिना किसी कारण के विगत परिपाठी से हट गए हैं तथा परिणामस्वरूप परिकलित क्षति रहित कीमत औचित्यपूर्ण कीमत से कम रही है। आवेदक का यह कहना है कि वही वर्तमान मामले में भी हो सकता था। आवेदक प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे कारण बताते हुए अपनाए गए सिद्धांत का औचित्य बताने का निर्देश दें कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकार्ता द्वारा अपनाया गया सिद्धांत घरेलू उद्योग के दावों को सीधे रद्द करने के बजाए अनुचित है तो वर्तमान जांच अपर्याप्त क्यों है।
- v. पाटनरोधी उपाय प्रतिस्पर्द्धा विरोधी नहीं हैं। घरेलू उद्योग पाटन की अनुचित परिपाठी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। पाटन अनुचित है और ऐसे पाटन के विरुद्ध समाधान की मांग करना अनुचित नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त देशों से आयात पाटिट कीमतों पर हैं और इसीलिए पाटनरोधी उपायों के अध्यधीन हैं। वस्तुतः पाटनरोधी उपाय उचित प्रतिस्पर्द्धा का ही संवर्धन करते हैं। "उचित व्यापारिक क्षेत्र" प्रदान करने के लिए पाटनरोधी अपेक्षित है।
- vi. वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा होने के नाते केवल परिवर्तित परिस्थितियों की समीक्षा तक सीमित है जो पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए औचित्यपूर्ण है। इसकी प्रकृति के अनुसार, समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित होगी कि क्या ये स्थितियां, जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद थीं, उस सीमा तक बदल गई हैं कि शुल्क की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन संबंध सामानों की पहुँच कीमत में गिरावट के कारण पूर्व जांच की तुलना में बढ़ गए हैं और पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाने के लिए वह पर्याप्त आधार है क्योंकि वर्तमान पाटन तथा क्षति मार्जिन लागू पाटनरोधी शुल्क से अधिक है।

47. घरेलू उद्योग ने समीक्षा के आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वर्तमान उपाय पाटन का सामना करने के लिए अपर्याप्त है जो कि क्षति पहुँचा रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उस सीमा तक सुधार नहीं हुआ है जो यूरोपीय संघ से गहन पाटन के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद होना चाहिए था।
- ii. घरेलू उद्योग के पास भारत में कुल मांग से कहीं अधिक क्षमता है, परंतु फिर भी वह अच्छा बाजार हिस्सा लेने में सक्षम नहीं है। मालसूची भी इकट्ठी हो रही है।
- iii. वर्तमान पहुँच कीमत आधार वर्ष में विद्यमान पहुँच कीमत से कम है। वर्तमान आवेदन के लिए जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत पहुँच मूल्य से अधिक है।
- iv. यूरोपीय संघ से आयात पाटिट कीमतों पर काफी मात्रा में देश में आते रहे हैं और मौजूदा उपायों के बाद भी प्रस्तावित जांच की अवधि में पूर्ण रूप से आयात काफी बढ़े हैं।

- v. भारत में आने वाले कुल आयातों में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से ने भी वृद्धि दर्शाई है।
- vi. यूरोपीय संघ से वर्तमान आयात काफी पाटिंग कीमतों पर हैं। पाटन मार्जिन यूरोपीय संघ की पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की तुलना में *** प्रतिशत से बढ़कर *** प्रतिशत हो गया।
- vii. जांच की अवधि में कीमत कटौती काफी और सकारात्मक है। कीमत कटौती वर्तमान जांच की अवधि में *** प्रतिशत से *** प्रतिशत तक सकारात्मक रही जो कि पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि थी।
- viii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यावधि समीक्षा के प्रपत्र के अनुसार क्षति रहित कीमत/पहुँच कीमत में परिवर्तन मध्यावधि समीक्षा के लिए अपेक्षित परिवर्तित परिस्थितियां बनाने के लिए पर्याप्त हैं।
- ix. वर्तमान मामले में एनआईपी और पहुँच कीमत, दोनों परिवर्तित हुए हैं।
- x. पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश प्राधिकारी द्वारा मई, 2014 में की गई थी और वह वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2014 में लगाया गया था। आयात कीमत पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत कम वृद्धि को छोड़कर तभी से कम होती रही है, परंतु वह आधार वर्ष से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, आयात मात्रा 2014-15 से बढ़ रही है। यद्यपि, आयात मात्रा *** मी. टन तक बढ़ी है, तथापि, आयात कीमत *** रुपए प्रति मी. टन तक कम हुई है। साथ ही, पहुँच मूल्य पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि से *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन तक कम हुआ है।
- xi. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत भी कम हुई है।
- xii. तथापि, पहुँच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में गिरावट से अधिक है। परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन *** प्रतिशत (** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन) से बढ़कर *** प्रतिशत (** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन) हो गया जो कि पहले से ही लागू पाटनरोधी शुल्क से अधिक है और पाटन सामना करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है।
- xiii. उपर्युक्त तथ्य परिवर्तित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप शुल्क की मात्रा बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार बनाते हैं।
- xiv. यदि यह परिदृश्य बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

48. विविध अनुरोधों के संबंध में वर्तमान जांच की अवधि में यूरोपीय आयोग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- घरेलू उद्योग प्रभावी बाजार स्थिति तथा कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्द्धा को अलग करने के लिए प्रयास कर रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ और चीन से संबद्ध सामानों पर शुल्क पहले ही लागू हैं तथा रूस के विरुद्ध जांच चल रही है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के आयातों पर शुल्क में वृद्धि से केवल आपूर्ति और उपभोक्ता के विकल्प का स्रोत प्रतिबंधित होगा।
49. किसी भी नियांतक, आयातक, उपभोक्ता अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच के क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. जहां तक कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए एकाधिकार के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन उचित व्यापार सुनिश्चित करना है और घरेलू उद्योग को एक व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना है। यह न तो आयात को प्रतिबंधित करने और न ही उत्पादों की विक्री कीमत में अनौचित्यपूर्ण वृद्धि करने के लिए कोई उपाय है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन संबद्ध देश से नियांतकों द्वारा अपनाई गए पाटन की अनुचित व्यापार परिपाठी के विरुद्ध घरेलू उद्योग को व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना है।
51. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को उपयुक्त स्थानों पर इस विवरण में अन्यत्र हल कर दिया गया है।
- छ. पाटन का मूल्यांकन – सिद्धांत तथा सामान्य मूल्य, नियांत कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण
- झ.1 घरेलू उद्योग के विचार

52. वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- घरेलू उद्योग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद संबंध देश में विद्यमान संबंध सामानों की लागत और कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। यह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
 - याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग की कञ्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग मानदंडों को मानते हुए भारत में उत्पादन लागत के आधार पर यूरोपीय संघ में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
 - आवेदक ने विश्व से भारत में आयात और नाइट्रिक एमिड के लिए घरेलू उद्योग की कीमत के संबंध में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार कास्टिक सोडा और अमोवनिया की कञ्ची सामग्री की कीमत मानी है। संबंध देश में विद्यमान विद्युत दरों को अपनाया गया है। अन्य सभी परिवर्तन लागत घरेलू उद्योग की लागत पर हैं जो विक्री, वितरण और प्रशासनिक खर्चों के लिए विधिवत समायोजित की गई हैं। 5 प्रतिशत का लाभ भी जोड़ा गया है।
 - संबंध देश से औसत आयात कीमत के आधार पर और उसके बाद उद्योग में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर उचित समायोजन करके निर्यात कीमत निर्धारित की गई है ताकि वह सामान्य मूल्य से तुलनीय हो।
 - पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी अधिक है। वह पिछली निर्णायक समीक्षा जांच की तुलना में *** प्रतिशत तक अधिक है।
 - जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटन से संबंधित साक्ष्य इस तर्क का समर्थन नहीं करते कि यूरोपीय संघ से पाटन बढ़ा है और यह कि वर्तमान शुल्क उससे हुई क्षति को समाप्त नहीं करता, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि कानून के तहत पाटन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आयातों की मात्रा अथवा पाटन मार्जिन के संदर्भ पर विचार किया जाता है। आयात मात्रा लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बाद भी काफी बढ़ी है।
 - जहां तक पाटन मार्जिन का संबंध है, यद्यपि, याचिकाकर्ता ने पाटन मार्जिन में वृद्धि सिद्ध की है, तथापि, वह अन्यथा दर्शने के लिए यूरोपीय उत्पादकों के लिए है।

ज्ञ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

53. यूरोपीय आयोग ने अनुरोध किया है कि पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस तर्क का समर्थन नहीं करते कि यूरोपीय संघ से पाटन बढ़ा है तथा उससे हुई क्षति को वर्तमान शुल्क समाप्त नहीं करता।

ज्ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, निर्यातिक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित तथ्य आधार बना सकते हैं:
- व्यापार की सामान्य अवधि में निर्यातिक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत।
 - निर्यातिक देश अथवा उपयुक्त तीसरे देश के क्षेत्र से निर्यातित समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत।
 - प्रशासनिक विक्री और सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त रूप से जोड़कर मूल देश में उपर्युक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

ज्ञ.3.1 सामान्य मूल्य

55. कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार, प्राधिकारी को यूरोपीय संघ में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में खपत के लिए बनाए गए उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में वास्तविक विक्री कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। यूरोपीय संघ में किसी भी निर्यातिक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत न करके प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में समान वस्तु की वास्तविक विक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, विक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित कर उत्पादन लागत के आंकलनों पर विचार करके निर्मित किया है।

ज्ञ.3.2 निर्यात कीमत

56. संबंद्ध देश से किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत के ब्यौरे देकर कोई सूचना नहीं दी है। अतः प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर यूरोपीय संघ के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर, उचित समायोजन करने के बाद निर्धारित की गई है। इस प्रकार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मी. टन है।

ज्ञ.3.3 पाटन मार्जिन

57. इस प्रकार, कारखानागत स्तर पर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर यूरोपीय संघ से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
1	परिवर्तन दर	अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए	66.70
2	सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
3	निवल निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
4	पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
5	पाटन मार्जिन	%	***
6	पाटन मार्जिन	% रेंज	25 – 35

ज. क्षति मूल्यांकन, क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क के लिए सिद्धांत

ज. 1 क्षति निर्धारण

ज.1.1 घरेलू उद्योग के विचार

58. वर्तमान जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:
59. घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2016 से जून, 2017 तक की अवधि को जांच की अवधि मानते हुए विधिवत दस्तावेजयुक्त याचिका दायर की थी। तथापि, प्राधिकारी ने अक्टूबर, 2016 से सितंबर, 2017 को जांच की अवधि मानते हुए जांच की शुरूआत की। तदनुसार, आवेदक ने अद्यतन अनुबंध दायर किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दर्शाया गया है:
- संबंद्ध देश से आयात पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद पूर्ण रूप में बढ़े हैं।
 - क्षति की अवधि में पहुँच मूल्य कम हुआ है।
 - भारत में आने वाले कुल आयातों में संबंद्ध आयातों का बाजार हिस्सा भी बढ़ा है।
 - आयातों से वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद घरेलू कीमतों में काफी कटौती हो रही है।
 - आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है। इस प्रकार, आयातों से बाजार में काफी कम पर बिक्री हो रही है।
 - घरेलू उद्योग की औसत मालसूची *** मी. टन से बढ़कर *** मी. टन हो गई है।

- vii. इस तथ्य के बावजूद कि संबंध देश से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क काफी समय से लागू रहा है, घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति हुई है और इस प्रकार, बढ़ी हुई दर पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता सिद्ध है।
- viii. शुल्कों की मात्रा में कमी करने अथवा हटाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की संभावना रहेगी।
- ix. मौजूदा उपाय पाटन का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे जो कि क्षति पहुँचा रहा है।
- x. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद विचाराधीन उत्पाद का इसके सामान्य मूल्य से कम पर भारत में निर्यात निरंतर हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है।
- xi. वर्तमान शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए अब पर्याप्त नहीं है; घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत काफी बढ़ी है और इसीलिए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा संशोधित किए जाने/बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- xii. चूंकि, वर्तमान जांच पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा तथा संशोधन के लिए है, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा एनआईपी के निर्धारण में दिए गए स्तर तक उसके निष्पादन में सुधार करने से रुक रहा है। यद्यपि, कुछ मानदंडों में प्रवृत्तियां सकारात्मक हो सकती हैं, तथापि, घरेलू उद्योग निवेश पर आय ("आरओआई") के इष्टतम से कम स्तर पर आय कर रहा है और लगभग वह स्थिर रह रहा है जो वर्तमान पाटन का निरंतर क्षतिकारक प्रभाव दर्शाता है। ऐसे अन्य कारक भी हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। आयात मात्रा काफी बढ़ा है, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है, पहुँच कीमत पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में थोड़ी सी वृद्धि को छोड़कर, 2014 में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने से कम होती रही है। परिणामस्वरूप, क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है जो अब लागू पाटनरोधी शुल्क से अधिक है।
- xiii. आवेदक ने यूरोपीय संघ के विनियम 3.5 का भी संदर्भ दिया है जिसमें पूर्व पाटन के तथ्य पर विचार करने का प्रावधान है तथा इस तथ्य पर भी विचार करने का प्रावधान है कि घरेलू उद्योग क्षति का मूल्यांकन करते समय पाटन के विगत कुप्रभावों से लौटने की प्रक्रिया में है।
- xiv. जहां तक यूरोपीय संघ की यूनिट कीमत का अन्य देशों की कीमत से अधिक होने के तर्क का संबंध है, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि यूरोपीय संघ से संबंध सामानों की आयात कीमत चीन और रूस से आयात कीमत से कम है। कीमत कटौती सकारात्मक और काफी होने के नाते उसका औचित्य बनाती है।
- xv. जहां तक उन दावों का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि वर्तमान में कम कीमत और बिक्री लागू पाटनरोधी शुल्क से अधिक है जो लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की वृद्धि की आवश्यकता को दर्शाता है।
- xvi. यूरोपीय आयोग ने किसी अन्य कारक का मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। घरेलू उद्योग को क्षति पूरी तरह से यूरोपीय संघ से पाटित आयातों के कारण है।
- xvii. क्षमता में वृद्धि को भारत में मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। वह अच्छा व्यापारिक निर्णय है। याचिकाकर्ता की क्षमता जांच की अवधि में 70800 मी. टन की स्थापित भारतीय मांग की तुलना में *** मी. टन है।

ज.1.2 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री की मात्रा और बिक्री मूल्य तथा घरेलू उद्योग का लाभ, सभी वृद्धि दर्शाते हैं।
- तथाकथित रूप से पाटित यूरोपीय संघ के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है क्योंकि यूनिट कीमत हमेशा चीनी और रूसी आयातों, दोनों की कीमत से तथा सभी आयातों की औसत यूनिट कीमत से भी अधिक रही है। यह घरेलू उद्योग की अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने की क्षमता में मिलाकर किसी नकारात्मक प्रभाव का न होना दर्शाता है।

- iii. घरेलू उद्योग के सकारात्मक आर्थिक संकेतकों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
- iv. क्षति, यदि कोई हुई है तो वह घरेलू उद्योग के अन्य कारकों के कारण है न कि यूरोपीय संघ से पाठित आयातों के कारण।
- v. घरेलू उद्योग ने उस समय अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2015-16 में निवेश किए जब यदि ज्यादा नहीं तो पहले ही घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी थी।

ज.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है।
 - (क) पाठित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाठित आयातों का प्रभाव; और
 - (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाठित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाठित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाठित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाठित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
62. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर इस प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में कार्रवाई की गई है।
63. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित क्रृष्णात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"

64. क्षति की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबंध देश से संबंध सामानों के वर्तमान पाठित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच पाटन और क्षति, यदि कोई है, के बीच कारणात्मक संपर्क तथा क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल कर देता है। तदनुसार, पाठित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

क. घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग और बाजार हिस्से का मूल्यांकन

65. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में भारत में मांग अथवा स्पष्ट खपत को ध्यान में रखा है। इस प्रकार, मूल्यांकित की गई मांग और निम्नलिखित तालिका में दी गई स्थिति क्षति की अवधि में वृद्धि दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की विक्री	मी. टन	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	मी. टन	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	मी. टन	***	***	***	***

संबंद्ध देश से आयात – यूरोपीय संघ	मी. टन	1,706	1,869	5,746	3,696
पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जन. गण.	मी. टन	11,432	12,688	5,683	7,925
जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क जांच चल रही है, उस देश से आयात – रूस	मी. टन	-	192	4,034	4,152
अन्य देशों से आयात	मी. टन	-	21	24	24
कैप्टिव सहित कुल मांग/खपत	मी. टन	55,265	62,772	63,763	68,515
घरेलू उद्योग की विक्री	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	%	***	***	***	***
संबंद्ध देश से आयात – यूरोपीय संघ	%	3.09	2.98	9.01	5.39
पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जन. गण.	%	20.69	20.21	8.91	11.57
जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क जांच चल रही है, उस देश से आयात – रूस	%	-	0.31	6.33	6.06
अन्य देशों से आयात	%	-	0.03	0.04	0.04
कुल हिस्सा	%	100.00	100.00	100.00	100.00

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. विचाराधीन उत्पाद की मांग ने पूरी क्षति की अवधि में वृद्धि दर्शाई है।
- ii. संबंद्ध देश से आयात जांच की अवधि में गिरावट दर्ज करने से पूर्व लगातार बढ़े हैं। वर्ष 2016-17 (अर्थात् जांच की अवधि से तक्ताल पूर्व वर्ष) के दौरान आयातों में काफी उछाल था। संबंद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 5.39 प्रतिशत तक कम होने से पूर्व 3.09 प्रतिशत से बढ़कर 9.01 प्रतिशत हो गया।

ख) आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

67. पाटनरोधी नियमाली के अनुबंध-II(ii) में यह प्रावधान है कि पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करने की अपेक्षा है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा उत्पादन के अनुपात में अथवा भारत में खपत की दृष्टि से पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। आयातों और बाजार हिस्से के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबंद्ध देश से आयात – यूरोपीय संघ	मी. टन	1,706	1,869	5,746	3,696
पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश से आयात – चीन जन. गण.	मी. टन	11,432	12,688	5,683	7,925
जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क जांच	मी. टन	-	192	4,034	4,152

चल रही है, उस देश से आयात – रूप					
अन्य देशों से आयात	मी. टन	-	21	24	24
कुल आयात	मी. टन	13,138	14,770	15,488	15,797
के संबंध में आयात					
कुल आयात	%	12.98	12.65	37.10	23.40
कुल भारतीय उत्पादन	%	3.29	3.16	9.68	5.76

68. प्राधिकारी उपर्युक्त से यह नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 217 प्रतिशत तक बढ़ी है। इसी प्रकार, कुल आयातों में संबंद्ध देश से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 12.98 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 37.10 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुँचने के बाद जांच की अवधि में 23.40 प्रतिशत तक बढ़ गया। संबंद्ध देश से पाठित आयातों की मात्रा भारत में उत्पादन के अनुपात में उसी अवधि के दौरान आधार वर्ष में 3.29 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 5.76 प्रतिशत तक हो गयी।

ख. कीमत प्रभाव

69. कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली का अनुबंध-II(ii) नीचे दिया गया है:

“जहाँ तक नियम के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाठित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

70. संबंद्ध देशों से पाठित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल विक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबंद्ध देश से संबंद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

71. कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाठित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत का ह्रास करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस संबंध में, घरेलू उद्योग के व्यापार के समान स्तरों पर सभी निवल छूटों और करों की औसत कीमत विक्री और उत्पाद के पहुँच मूल्य के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

72. यह देखा जाएगा कि संबंद्ध देश से कीमत कटौती 2015-16 और जांच की अवधि में सकारात्मक है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच की अवधि
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	39,876	39,192	35,743	36,819
निवल विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	(***)	(***)	***	***
	रेंज %	(5-10)	(0-5)	5-10	5-10

ख. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबंध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ह्रास हो रहा था और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में आयातों की पहुँच कीमत के साथ क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना की है और निम्नलिखित तालिका में दर्शाई है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	96	101
निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	102	108
पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	39,876	39,192	35,743	36,819
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	90	92

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के स्तर से कम है। यद्यपि, कीमत न्यूनीकरण और ह्रासमान प्रभाव दर्शनीय नहीं हैं।

ग. कम कीमत पर बिक्री

75. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा निकालने के लिए संबंध सामानों के पहुँच मूल्य से उसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। विश्लेषण यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबंध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम थी जो सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि* (भारतीय रुपए)	जांच की अवधि* (अमेरिकी डॉलर)
पहुँच कीमत	प्रति मी. टन	36,819	552.01
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी. टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी. टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-5	0-5

* अक्टूबर, 2016 – सितंबर, 2017

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंध देश से पाठित आयात घरेलू उद्योग की क्षमता/उचित कीमत से कम कीमतों पर भारत में आ रहे हैं और इस प्रकार, कम कीमत पर सकारात्मक विक्री हो रही है।

ग.) घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

77. पाठनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षमता के निर्धारण में संबंध सामानों के घरेलू उत्पादक (उत्पादकों) पर संबंध सामानों के आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। उपर्युक्त नियम का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, पाठन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारक और तत्वों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

78. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षमता संबंधी मानदंडों की जांच की है।

क.) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्री

79. घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन पर पाठित आयातों के प्रभाव और घरेलू उत्पादन की मात्रा की जांच कुल उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री के संदर्भ में की गई है। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री मात्रा निम्नलिखित रही है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	111	111
उत्पादन – सोडियम नाइट्राइट	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	122	129
उत्पादन - संयंत्र (एसएनआई + एसएनए)	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	118	126
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	107	114
घरेलू विक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	122	130

80. उपर्युक्त तालिका में आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग ने 2015-16 में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और तभी से क्षमता उसी स्तर पर रही है। संबंधित उत्पाद का उत्पादन पूरी क्षमता की अवधि में बढ़ा है।
- घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग भी पूरी क्षमता की अवधि में बढ़ा है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री भी क्षमता की अवधि में बढ़ी है।

ख.) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह

81. क्षति की अवधि के दौरान निवेश पर आय, ब्याज पूर्व एवं ब्याज के बाद लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
विक्री की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	98	96	101
विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	104	102	108
लाभ/हानि	रु./मी. टन	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	-100	237	233	282
लाभ/हानि	लाख रु.	(***)	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	-100	289	283	366
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	671	608	814
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	782	816	941
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	608	516	636

82. उपर्युक्त तालिका में आंकड़ों की जांच से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों की स्थिति से बाहर आया है और लाभ कमाता रहा है। परिणामस्वरूप ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि हुई है।

ग) मांग में बाजार हिस्सा

83. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कैप्टिव सहित मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग की विक्री	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	%	***	***	***	***
संबंध देश – यूरोपीय संघ	%	3.09	2.98	9.01	5.39
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाला देश – चीन जन. गण.	%	20.69	20.21	8.91	11.57

जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क जांच चल रही है, उस देश से आयात - रूस	%	-	0.31	6.33	6.06
अन्य देश	%	-	0.03	0.04	0.04
कुल हिस्सा	%	100.00	100.00	100.00	100.00

84. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष के बाद आंशिक रूप से बढ़ा है तथा उसके बाद कुल मिलाकर समान रहा है, तथापि, यूरोपीय संघ से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 3.09 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 5.39 प्रतिशत हो गया जो कि 2016-17 में 9.01 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुँच गया।

घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

85. घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, उसकी उत्पादकता और दी गई मजदूरी का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	101	101
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	135	137
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	121	128
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	122	129

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) घरेलू उद्योग में रोजगार क्षति की अवधि में कुल मिलाकर समान रहा है।
- (ख) मजदूरी पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है।
- (ग) प्रति कर्मचारी एवं प्रति दिन उत्पादकता में पूरी क्षति की अवधि में सुधार आया है।

ड) मालसूची

87. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	198	217	385

88. घरेलू उद्योग में औसत मालसूची पूरी क्षति की अवधि में बढ़ी है।

च) वृद्धि

89. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों से नोट करते हैं कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, बिक्री कीमत, लाभप्रदता और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में अधिक हुई है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि*
वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)					
उत्पादन	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	%	-	***	***	***
बिक्री की लागत	%	-	(***)	(***)	***
बिक्री कीमत	%	-	***	(***)	***
प्रति यूनिट लाभ/हानि	%	-	***	***	(***)
निवेश पर लाभ	%	-	***	(***)	***

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

90. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पूंजी निवेश जुटाने के लिए उनकी क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, यदि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का हल नहीं किया जाता है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित सामग्री की कीमतें निवल बिक्री वसूली और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। तथापि, संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ नहीं प्रतीत होता क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद काफी अधिक भी है।

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
1	परिवर्तन दर	अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए	66.70
2	सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
3	निवल निर्यात कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
4	पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
5	पाटन मार्जिन	%	***
6	पाटन मार्जिन	% रेंज	25 – 35

क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

93. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/अंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की इस क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबंध श्वेत्र से संबंध आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है। इस प्रकार, क्षति मार्जिन निम्नलिखित रूप में निकाला गया है:

विवरण	यूनिट	अक्तूबर, 2016 से सितंबर, 2017*
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
पहुँच कीमत	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	552.01
क्षति मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/मी. टन	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	% रेंज	0-5

क. क्षति संबंधी निष्कर्ष

94. पाटनरोधी नियमावली के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- पाटित कीमतों पर संबंध देश से संबंध सामानों का आयात जांच की अवधि में गिरावट दर्ज करने से पूर्व लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयातों में काफी उछाल था (अर्थात् जांच की अवधि से तत्काल पूर्व वर्ष)। संबंध देश से आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 5.39 प्रतिशत तक घटने से पूर्व 3.09 प्रतिशत से बढ़कर 9.01 प्रतिशत हो गया।
- कीमत कटौती सकारात्मक है और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन भी बढ़ा है।
- तथापि, संबंध देश से आयात से घरेलू उद्योग पर कीमत मानदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उनकी निवल विक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।
- घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, विक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, क्षमता, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय के संदर्भ में सुधार हुआ है।
- आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के स्तर से कम होने के बावजूद इन आयातों से कोई कीमत न्यूनीकरण और/अथवा ह्रास नहीं हुआ है।

ज.3 कारणात्मक संपर्क और अन्य कारक

95. नियमावली के अनुबंध-II में कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"यह दर्शाया जाना चाहिए कि पाटित आयात पाटन के प्रभाव के माध्यम से जैसा कि उपर्युक्त पैरा (ii) और (iv) में निर्धारित है, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी उन पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच भी करेंगे जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं और इन कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में जो कारक संगत होने चाहिए, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपायियां, प्रौद्योगिकी में विकास और नियर्ति निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल होगी।"

96. प्राधिकारी ने यह भी जांच की कि क्या नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

क. पाठित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

97. चीन से आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। घरेलू उद्योग ने रूस से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर की है। प्राधिकारी अलग से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अन्य देशों से आयात मात्रा में काफी नहीं हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए किए गए दावे के अनुसार क्षति के कारण के रूप में नहीं माने जा सकते।

मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

98. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में कोई नकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसके बजाए, इसमें वृद्धि हुई है और सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। इस प्रकार, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान करने वाला कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, खपत के पैटर्न में परिवर्तन वह कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति के दावे में योगदान करे।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा

99. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार क्षति में योगदान किया हो।

प्रौद्योगिकी में विकास

100. इस उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुई है और न ही आगे भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार क्षति का कारक नहीं है।

ड. निर्यात निष्पादन

101. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करता है। निर्यात की मात्रा केवल क्षति की अवधि में बढ़ी है और इसीलिए वह घरेलू उद्योग द्वारा किए दावे के अनुसार क्षति के लिए उत्तरदायी कारक नहीं हो सकता।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

102. प्रति दिन उत्पादकता तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता में निरंतर क्षति की अवधि में सुधार हुआ है और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार क्षति का कारण नहीं हो सकती।

कोई अन्य कारक

103. वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा *** मी. टन से बढ़ाकर *** मी. टन किया गया क्षमता विस्तार पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में एक कारक की तुलना में अधिक क्षति मार्जिन के लिए उत्तरदायी एक कारक है।

104. जांच की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एकत्रित जांच के अनिवार्य तथ्य और वर्तमान प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण हितवद्ध पक्षकारों को प्रकट किए गए थे ताकि वे हितवद्ध पक्षकार इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

ट. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

105. हितवद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पहले ही पूर्व में उठा दिए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

106. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:

- वर्तमान जांच का क्षेत्र पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः निर्धारण करने तक ही सीमित है क्योंकि यह मध्यावधि समीक्षा जांच है।
- वर्तमान जांच के क्षेत्र को पूर्ण क्षति विश्लेषण तक बढ़ाना, मानो यह पाटनरोधी शुल्क नए सिरे से लगाए जाने के लिए एक याचिका थी और इस बात का मूल्यांकन कि घरेलू उद्योग का वास्तविक क्षति हुई है अथवा नहीं, किसी कानूनी और वास्तविक आधार के बिना है।
- प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का परिकलन घरेलू उद्योग की मानक लागत पर विचार करते हुए किया गया है जो कानून के अनुरूप नहीं है। प्राधिकारी को वास्तविक उत्पादन लागत अपनाए जाने की अपेक्षा है।

- न कि मानक उत्पादन लागत। बिना किसी पूर्वाग्रह के एनआईपी कम बताई गई है जिससे कम सामान्य मूल्य बनता है। प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित परिणामी पाटन मार्जिन काफी कम है।
- iv. निर्धारित क्षति रहित कीमत बहुत कम है। एनआईपी को विभाजन सिद्धांत में संशोधन करके और खर्चे के कई घटकों को अलग करके अनुपयुक्त रूप से कम किया गया है। उस सिद्धांत में परिवर्तन करना अनुपयुक्त होगा जो मूल जांच के समय निर्धारित किया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन और यूरोप से सोडियम नाइट्राइट के मामले में पूर्व में जांचें की हैं और एनआईपी निर्धारित किया है।
 - v. संबंद्ध देश से आयात पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़े हैं और भारत में आने वाले कुल आयातों में संबंद्ध आयातों का बाजार हिस्सा भी बढ़ा है।
 - vi. पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन पिछली निर्णायिक समीक्षा जांच की तुलना में बढ़ा है।
 - vii. कीमत कटौती -3.13 प्रतिशत से 9.55 प्रतिशत हो गई है जो पिछली निर्णायिक समीक्षा जांच की जांचावधि में थी। आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के स्तर से कम है। पहुँच मूल्य पिछली निर्णायिक समीक्षा जांच की जांचावधि से 97.71 अमेरिकी डॉलर/मी. टन तक घट गया है।
 - viii. घरेलू उद्योग की एनआईपी भी कम हुई है। तथापि, पहुँच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत में गिरावट से अधिक है। इस प्रकार, आयातों से बाजार में काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
 - ix. क्षति मार्जिन बढ़ा है और वह पहले से ही लागू पाटनरोधी शुल्क से अधिक है। इस प्रकार, क्षति मार्जिन में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को कम करने की सीमा तक पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं।
 - x. याचिकाकर्ता ने दिनांक 19 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 15/06-2016-डीजीएडी की वर्तमान एमटीआर जांच और पिछली चीनी निर्णायिक समीक्षा जांच के बीच किए गए निष्कर्षों की तुलना की है।
 - xi. कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनके संबंध में निर्णायिक समीक्षा जांच की तुलना में वर्तमान एमटीआर जांच में क्षति अधिक प्रमुख है। आयात निर्णायिक समीक्षा जांच में आयातों में गिरावट की तुलना में निरंतर बढ़ रहे हैं। निर्णायिक समीक्षा जांच में बिक्री कीमत लागतों में वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती रही। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन की समीक्षा करते हुए निरंतर पाटन और निरंतर क्षति का निष्कर्ष निकाला है।
 - xii. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण करते समय संभावित मानदंड की जांच भी नहीं की है। यद्यपि, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण में विगत सभी एमटीआर जांचों में संभावना की जांच की है, तथापि, याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में उसकी उपेक्षा करने का कारण समझ में नहीं आया।
 - xiii. गहन पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना आसन्न है क्योंकि आयातों की मात्रा शुरू से ही और यहां तक कि वर्तमान जांच में भी काफी रही है। यूरोपीय उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं हैं और संबंद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के कुल कारोबार में निर्यातों की प्रतिशतता काफी अधिक है। यदि ये पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाए जाते हैं तो आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी न्यूनीकरण और/अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ेगा।
 - xiv. आयातों से घरेलू कीमतों की काफी कटौती हो रही है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू है। ऐसी संभावना है कि भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के कारण वह जारी रहेगी और घरेलू उद्योग की उसकी कीमतें और बढ़ाने के लिए मजबूर कर देंगी, यदि पाटनरोधी शुल्क उसकी मात्रा में वृद्धि किए बिना जारी रखने की अनुमति दी जाती है।
 - xv. प्राधिकारी की इस चिंता के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, क्षमता, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में सुधार हुआ है और यह कि निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है; यह अनुरोध है कि चूंकि वर्तमान याचिका समीक्षा तथा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन के लिए है, अतः प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग को इष्टतम स्तरों तक उसका निष्पादन सुधारने से रोक रहे हैं।

- xvi. जहां तक वर्ष 2015-16 के दौरान क्षमता विस्तार संबंधी तर्क का संबंध है, यह अनुरोध है कि क्षमता में वृद्धि भारत में मांग में वृद्धि पर विचार करते हुए ली गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच होने के नाते कारणात्मक संपर्क देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का प्रति यूनिट लागत ढांचा उस तरीके से नहीं बढ़ा है कि वह यह दर्शा सके कि घरेलू उद्योग द्वारा किया गया क्षमता विस्तार दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी है।
- xvii. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि घरेलू उद्योग को क्षति का पूरा कारण पाटित आयात होने चाहिए और उन कानूनी अपेक्षाओं की उपेक्षा की है कि पाटन घरेलू उद्योग का क्षति का केवल एक कारण होना चाहिए।
- xviii. पूर्व निर्णायिक समीक्षा के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में प्रमुख परिवर्तन आए हैं जो वर्तमान लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता का औचित्य बनाते हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

107. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण संबंधी निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:
- i. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, यूरोपीय संघ से आयात 2016-17 तक मात्रा में बढ़े हैं, परंतु फिर उन्होंने बाजार हिस्से में गिरावट के साथ-साथ जांच की अवधि में काफी गिरावट (****) दर्ज की।
 - ii. जहां तक घरेलू कीमतों पर यूरोपीय संघ के आयातों के प्रभाव का संबंध है, यद्यपि, यह प्रतीत होता है कि कीमत कटौती मार्जिन 2015-16 में और जांच की अवधि में सकारात्मक हुआ (यद्यपि यह कम है), प्राधिकारी ने पाया कि यूरोपीय संघ के आयातों में घरेलू उद्योग को कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा कीमत ह्रास नहीं किया है। वस्तुतः घरेलू उद्योग तब भी अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ था, इस प्रकार, दावे को अवैध मानते हुए कि यूरोपीय संघ के आयातों की कीमत से उन्हें घरेलू कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
 - iii. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू बिक्री मानी गई अवधि के दौरान बढ़ी है।
 - iv. इसी प्रकार, लाभप्रदता सकारात्मक हो गई और काफी बढ़ गई। विशेष रूप से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि "घरेलू उद्योग वित्तीय हानियों की स्थिति से बाहर आ गया है और लाभ कमा रहा है। परिणामस्वरूप ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि हुई है।"
 - v. जहां तक बाजार हिस्से का संबंध है, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा है और तभी से स्थिर रहा है।
 - vi. रोजगार भी कम नहीं हुआ। इसके विपरीत, मजदूरी बढ़ी है, यह दर्शते हुए कि यूरोपीय संघ के आयातों का घरेलू रोजगार बाजार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।
 - vii. ऊपर संक्षेप में दिए गए मानदंडों और प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियों की पिछली स्थिति से वर्तमान लाभदायक स्थिति में उठाकर पाटित आयातों के कारण क्षति का उपचार करने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं।
 - viii. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सही उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को क्षति यदि कोई है, 2015-16 में किए गए क्षमता विस्तार के कारण हो सकती है।
 - ix. यह अनुरोध है कि यूरोपीय आयोग ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 में किए गए प्रावधान के अनुसार अन्य कारकों से हुई पाटित आयातों के कारण क्षति, यदि कोई है, को अलग करने की आवश्यकता के संबंध में मुद्दा पहले ही उठाया था।
 - x. यूरोपीय आयोग मानता है कि ऐसा कोई घटक नहीं है जो पाटनरोधी शुल्कों के वर्तमान स्तर में वृद्धि का औचित्य बनाए, जो उसके सुधरे निष्पादन द्वारा दर्शाए गए अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

- xii. अतः इन परिस्थितियों में वर्तमान शुल्क का स्तर बढ़ाना डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 को भी भंग करना होगा।
- xiii. यूरोपीय आयोग का विश्वास है कि भारतीय प्राधिकारी यूरोपीय संघ के आयातों पर पहले से ही लागू पाटनरोधी शुल्क के स्तर में कोई परिवर्तन किए बिना वर्तमान मध्यावधि जांच को रद्द करेंगे।

प्राधिकारी द्वारा जांच

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं और प्रकटन विवरण में उनका पहले ही पूर्व में समाधान कर दिया गया है। उपर्युक्त जांच परिणाम पक्षकारों के तीन तर्कों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने संगत सीमा तक और अन्यत्र हितवद्ध पक्षकारों के जिन अनुरोधों का समाधान नहीं किया गया है, उनकी निम्नलिखित रूप में जांच की है:
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में एनआईपी के निर्धारण के लिए अपनाया गया सिद्धांत वही है जो पूर्व जांचों में निरंतर अपनाया गया है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में लागत के काफी अनुपात में कड़ी सामग्री की लागतों और यूटिलिटियों की लागत शामिल है जिनकी अनुमति वास्तविक के आधार पर दी गई है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि घरेलू उद्योग के पिछले कई वर्षों से पाटनरोधी जांचों के तहत कई उत्पाद हैं। दिनांक 12.05.2014 की अधिसूचना संख्या 15/1009/2012-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के दौरान यह पाया गया था कि कंपनी ने दो अलग-अलग संयुक्त उत्पादों अर्थात् सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के लिए आवंटन की भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनाई थीं। चूंकि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुवंध-III के तहत अपेक्षित सतत पद्धति नहीं अपनाई, अतः दोनों उत्पादों अर्थात् सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के संबंध में तभी से अन्य लागतों के आवंटन के लिए समान सिद्धांत अपनाया गया है और उसके बाद सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा दो भिन्न जांचों की तुलना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी का उद्देश्य सभी हितवद्ध पक्षकारों के लिए स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित करना है।

ग. निष्कर्ष

109. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और तर्कों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- संबंद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है। यहां तक कि क्षति मार्जिन लागू पाटनरोधी शुल्क की तुलना में अधिक है। तथापि, क्षति मार्जिन में वृद्धि आंशिक रूप से 2015-16 के दौरान किए गए क्षमता विस्तार के कारण है।
 - संबंद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ा है। तथापि, संबंद्ध देश से आयात से घरेलू उद्योग कीमत संबंधी मानदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि उनकी निवल विक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।
 - घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र सुधार है। उसके उत्पादन, विक्री, बाजार हिस्सा, लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने सतत वृद्धि दर्ज की है।

ड. सिफारिश

110. उपर्युक्त निष्कर्ष का अनुकूल दृष्टिकोण देते हुए प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि की सिफारिश नहीं करते हैं। तथापि, प्राधिकारी संबंद्ध देश से संबंद्ध सामानों के आयातों पर दिनांक 08.08.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 37/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं।
- इ.** **आगे की प्रक्रिया**
111. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2018

FINAL FINDINGS

Subject: Mid-Term Review investigation concerning imports of “Sodium Nitrite” originating in or exported from the European Union.

No. 7/12/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

The Original Investigation

1. Whereas, having regard to the Act and the Rules, the original investigation concerning imports of Sodium Nitrite (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration or PUC) originating in or exported from European Union and Taiwan, was initiated by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) vide Notification No. 54/1/2001-DGAD dated November 02, 2001. The Preliminary Findings were notified on February 01, 2002 and the provisional duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 34/2002-Customs dated March 28, 2002. The Authority notified final findings on October 28, 2002 recommending definitive antidumping duty on the subject imports of the subject goods. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 132/2002-Customs dated November 29, 2002.

The First Sunset Review

2. Subsequently, the Authority initiated sunset review investigations vide Notification No.15/6/2005—DGAD dated March 06, 2007 concerning imports from European Union (hereinafter also referred to as “subject country”). The Authority recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties on the subject imports from the subject country vide notification No.15/6/2005-DGAD, dated March 03, 2008 and Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No.49/2008-Customs, dated the April 11, 2008 on imports of the subject goods from the subject country.

The Second Sunset Review

3. Subsequently, the Authority initiated second sunset review investigations vide Notification No. 15/1009/2012- DGAD dated March 23, 2013. The Authority again recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties on the subject imports from the subject country vide Notification No. 15/1009/2012- DGAD, dated May 12, 2014 and the Ministry of Finance extended definitive antidumping duty vide notification No.37/2014- Customs, dated August 08, 2014 on imports of the subject goods from the subject country.

Present Mid-term Review investigation

4. M/s Deepak Nitrite Limited has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject country in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The applicant commands a major proportion in Indian production of the like article. The applicant has claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the previous investigation have changed significantly leading to a situation where the existing anti-dumping duties are no longer effective and that there is need of enhancement of the quantum of the anti-dumping duty in force.

5. The applicant has claimed that the existing measures are insufficient to counteract the dumping which is causing injury as a result of which significant volume of imports at dumped prices is claimed to be entering into India in spite of anti-dumping duty being in force. The applicant has further submitted that the subject imports are causing significant price undercutting even at the existing levels of antidumping duty and that the current injury margin is substantially higher than the current anti-dumping duty in force.
6. Based on *prima facie* examination of facts the Designated Authority initiated the Mid Term Review vide Notification No. 7/12/2017-DGAD dated 11th December, 2017.

B. PROCEDURE

7. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
8. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Petitioner. The Authority notified the Embassies of the subject country in India about the receipt of the application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule 5(5) of the AD rules. Initial petition was filed considering July, 2016 to June, 2017 as the POI. Based on the data provided by the petitioner, the case was initiated. However, since the data submitted in the application was not recent one for investigation purpose the period from October, 2016 to September, 2017 was taken as the POI for conducting the investigation. The petitioner accordingly updated the data.
9. The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters, importers and industry associations (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within forty days from the date of the letter.
10. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassy of subject country in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
11. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - a. BASF Aktiengesellschaft, Germany
 - b. Terra Nitrogen (UK) Ltd, UK
12. None of the producers/exporters from the subject country has filed the exporter's questionnaire response. However the European Commission has raised certain objections to the petition and initiation of the subject investigation.
13. Questionnaires were also sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - a. M/s Ahmedabad Chemicals
 - b. M/s Asiatic Industries
 - c. M/s Aries Dyechem Inds.
 - d. M/s Bakul Aromatics & Chemicals Limited
 - e. M/s B. I. Mehta
 - f. M/s Caffil Pvt. Ltd.
 - g. M/s Dintex Dyechem Limited
 - h. M/s Dynamic Industries Limited
 - i. M/s EnzelChem (I) Pvt. Ltd.
 - j. M/s Farmson Pharmaceuticals
 - k. M/s Indocol Chem Ltd.

1. M/s Island Veerchemie
- m. M/s Jansons Limited
- n. M/s KetulChem Pvt. Ltd.
- o. M/s Metrochem Industries,
- p. M/s Manish Chemicals
- q. M/s Parzin Chemicals Limited
- r. M/s Prabava Exports
- s. M/s Ravi Dyewear Co. Ltd.
- t. M/s Roha Dyechem
- u. M/s Savakashi Dye – O – Fab
- v. M/s SU – Vi Chemicals Ltd.
- w. M/s Suven Pharmaceuticals Limited
14. In response to the initiation notification, none of the above mentioned importers, users and associations have responded and filed the questionnaire response.
15. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
16. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
17. Further information was sought from the Petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary.
18. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigations.
19. The Non-injurious Price (hereinafter referred to as ‘NIP’) based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
20. Investigation was carried out for the period starting from October, 2016 to September, 2017 (12 months) (hereinafter referred to as the ‘period of investigation’ or the ‘POI’). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
21. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of subject goods during last three years, including period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S imports data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.
22. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in hearing held on 10th April, 2018. However, apart from the domestic industry, none of the other parties attended the oral hearing.
23. The submissions made by the interested parties to the extent considered relevant by the Authority have been addressed in this notification.
24. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
25. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

26. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD=Rs 66.70.

C. Product Under Consideration And Like Article

C.1 Views of the Domestic Industry

27. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of product under consideration and the like article:

- i. The instant investigation being a mid-term review investigation for examination of request for enhancement of the Anti-dumping duty in force, the product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations.
- ii. The product involved in the previous investigations and the present review investigation is ‘Sodium Nitrite’ in all its forms. Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, meat processing, textiles, etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get sodium nitrite. The product is odourless and soluble in water.
- iii. Sodium Nitrite falls within Chapter 28 of the Custom Tariff Act, 1975 under custom sub-heading 28.34.10 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- iv. There is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and subject goods imported into India. Sodium Nitrite produced by the domestic industry and imported into India are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. And the goods produced by the domestic industry and imported from the subject territory are like articles in accordance with the Rules.
- v. Hence the goods produced by the domestic industry and imported from the subject territory are like articles in accordance with the Rules.

C.2 Views of the Opposing Interested Parties

28. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.

C.3 Examination by the Authority

29. The Authority notes that the present investigation is a mid-term review investigation and the scope of the PUC under the present investigation is the same as the scope of product against which the anti-dumping duty is currently in force.
30. The product under consideration for the purpose of present investigation is Sodium Nitrite in all its forms as it was in the previous investigations including the second sunset review investigation.
31. Sodium Nitrite is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc. The subject goods are produced by using nitric acid obtained from nitrous oxide gas or ammonia at high temperature in presence of catalysts. The nitrous oxide is further absorbed in caustic soda/soda ash to get sodium nitrite. The product is odourless and soluble in water.
32. The product is classified under Customs Tariff heading 28.34.10 of Chapter 28 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
33. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation"

34. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions, uses and product specification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the similarity in manufacturing process and substitutability, the Authority holds that subject goods produced by the Domestic Industry are like article as per Rule 2(d) of the Rules to the ‘product under consideration’.

D. Scope Of Domestic Industry & Standing

D.1 Views of the Domestic Industry

35. The domestic industry has made following submissions with regard to domestic industry and standing:
- i. The applicant is an interested party as defined in Rule 2(c) of the Rules as it is a producer of the like article in India. In the relevant sunset review investigations Deepak Nitrite Ltd., was the petitioner and was found eligible as domestic industry by the Authority as it accounted for a major proportion of the production of the ‘Like Article’ in India.
 - ii. M/s Deepak Nitrite Ltd has filed the application for review for enhancement of anti-dumping duty. There are three other producers of Sodium Nitrite in the country, apart from the petitioner, namely, Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited, National Fertilizer Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. The Applicant however continues to be a major producer of the subject goods in India and commands 92.26% share in the Indian production in the POI and, therefore, constitutes domestic industry.
 - iii. The petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and further, is not related to any exporter or producer of the subject goods in European Union or any importer of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
 - iv. Therefore, for the purposes of this review, the Applicant satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

D.2 Views of the other Interested Parties

36. None of the exporters, importers, consumers and any other interested parties has filed any comment or submission with regard to standing of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

37. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:-

(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

38. The application was filed by M/s Deepak Nitrite Limited and was supported by Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited (PCPL) and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL). Further, there is one other producer of the subject goods apart from the applicant and supporter, namely, National Fertilizers Ltd.
39. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicant alone constitutes 92.11% of the total domestic production and with support of PCPL and RCFL, 96.10% of the total Indian production. Further, the petitioner has not imported the subject goods during the period of investigation, and, is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject country or any importer of the product under consideration in India.

Statement of Indian Production

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Petitioner	MT	***	***	***	***
	Index	100	121	122	129
Supporter's Production	MT	***	***	***	***
Punjab Chemicals	MT	***	***	***	***
Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd.	MT	***	***	***	***
Supporter's Production	Index	100	32	29	61
Petitioner including supporters	MT	***	***	***	***
	Index	100	114	114	123
Other Indian Producers (NFL)	MT	***	***	***	***
	Index	100	121	122	129
Total Indian Production	MT	51,922	59,088	59,334	64,143
	Index	100	114	114	124
Share in %					
Petitioner Share	%	***	***	***	***
Supporter's Share	%	***	***	***	***
Punjab Chemicals	%	***	***	***	***
Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd.	%	***	***	***	***
Petitioner including supporter	%	***	***	***	***
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Total Indian Production	%	100.00	100.00	100.00	100.00

40. In view of the above, the Authority holds that the applicant satisfies the standing requirements and constitutes domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

E. Issues Relating to Confidentiality

E.1 Views of the Domestic Industry

41. The domestic industry has made following submissions with regards to confidentiality:
- i. Sufficient non-confidential information with good cause has been provided in this regard. The practice adopted by the petitioner is consistent with the Designated Authority' past practice as well.
 - ii. In response to the changed POI via initiation notification no. F.No.7/12/2017-DGAD dated 11th December, 2017 in the subject matter, the petitioner had filed the updated annexures on January 20, 2018 and the relevant information with respect to injury margin and price undercutting has also been put on record.
 - iii. The petitioner has provided indexed information of selling price both in the petition and the updated annexures. The actual figures are business sensitive information and cannot be disclosed to other parties.

E.2 Views of the other Interested Parties

42. Various submissions made by the European Commission during the course of the present investigation with regard to transparency and confidentiality are as follows:

- i. Information provided in the non-confidential version of the petition is not sufficient to understand the dumping margin and the undercutting calculations and to fully exercise its right of defence.
- ii. No information has been provided with respect to injury margin and price undercutting as the relevant annexures are missing in the non-confidential version of the petition.
- iii. The petition does not contain any information on the selling price of the domestic industry, not even in the form of indexes/ranges.

E.3 Examination by the Authority

- 43. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
- 44. Various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality were examined. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
- 45. It is noted that disclosure of the commercially sensitive and confidential information provided by the interested parties to the Designated Authority to facilitate the investigation, will not be in order. The disclosure of confidential information relating to the selling price of the domestic industry is not warranted as it will provide undue advantage to its domestic as well as overseas competitors.

F. Miscellaneous Issues

F.1 Views of the Domestic Industry

- 46. The domestic industry has made following submissions with regard to various miscellaneous issues:
 - i. None of the European exporters has responded with prescribed questionnaire response. Thus, the Authority may consider the subject producers and exporters non-cooperative and decide the matter as per Rule 6(8) and may record its finding on the basis of facts available to it.
 - ii. These producers are very well aware that the actual dumping margin as per their data is materially higher than the “small” dumping margin claimed by the petitioner and that shall be determined by the Authority.
 - iii. The European Embassy had submitted certain objections prior to public hearing which has been duly filed. Since neither the embassy nor any other interested party were present during the public hearing, the Authority should not accept any written submissions filed by them.
 - iv. The Petitioner requests that the methodology adopted by the petitioner for allocation and apportionment of expenses must be accepted by the Authority and not modified suo-motu. Methodology adopted by the petitioner for apportionment of expenses has been put on record. The applicant has been consistently providing costing information following the methodology adopted in the present case. There have been various cases related to the product concerned wherein the Authority had accepted company’s methodology. However, in the past few cases, the Authority has deviated from its past practice without any reason and resultantly the non-injurious price computed has been lower than justified. The Applicant has the apprehension that the same might happen in the present case as well. The applicant humbly requests the authority to direct the domestic industry to justify the methodology adopted giving reasons as to why the present justification is insufficient in case the Authority considers that the methodology adopted by the petitioner is inappropriate, instead of outrightly rejecting the claims of the domestic industry.
 - v. Anti-dumping measures are not anti-competitive. The domestic industry is trying to eliminate unfair practice of dumping. Dumping is unfair and seeking redressal against such dumping cannot be considered unfair. The imports from the named countries are at dumped prices and therefore are subject

- to anti-dumping measures. In fact, anti-dumping measures promote fair competition only. Anti-dumping is required to provide a “level playing field”.
- vi. The present investigation being a mid-term review is limited to only review of the changed circumstances which justify the enhancement of quantum of anti-dumping duty. By its very nature, the review inquiry would be limited to see as to whether the conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such an extent that there is need to enhance the quantum of duty. The injury margin and dumping margin have increased as compared to the previous investigation due to the decline in landed price of subject goods and the same is a sufficient ground to enhance the quantum of anti-dumping duties as the present dumping as well as injury margin is higher than the anti-dumping duty in force.
47. The domestic industry has made following submissions with regard to grounds of review:
- i. Existing measure is insufficient to counteract dumping which is causing injury as the performance of the domestic industry has not improved to the extent it should have after imposition of ADD due to intensified dumping from EU.
 - ii. The DI has much more capacity than the total demand in India but still is not able to fetch a good market share. The inventories are also piling up.
 - iii. The current landed price is lower than the landed price prevailing in the base year. The selling price and cost of sales of the domestic industry in the POI for the purpose of present application are more than the landed value.
 - iv. The imports from European Union have continued to enter the country in significant volumes at dumped prices and that the imports have increased significantly in absolute terms in the proposed POI even after existing measures.
 - v. Market share of the subject imports in total imports entering India has also shown an increase.
 - vi. The current imports from European Union are at significant dumped prices. Dumping margin increased from *** % to ***% as compared to the last sunset review investigation of the European Union.
 - vii. The price undercutting is significant and positive in the period of investigation. Price undercutting became positive to *** % in POI of the current investigation from (*** %) , which was in the POI of the last sunset review investigation.
 - viii. As per the proforma of mid-term review issued by the Designated Authority, change in non-injurious price/landed value in itself is sufficient to constitute changed circumstances as required for a mid-term review.
 - ix. In the present case, the NIP and landed price, both, have changed.
 - x. The anti-dumping duty was recommended by the Authority in May, 2014 and the same was imposed by the Ministry of Finance in August, 2014. The import price has been declining since then except a small increase in the POI as compared to the preceding year but the same is much lower than the base year. Further, the import volume is increasing since 2014-15. While the import volume has increased by *** MT, the import price has decreased by Rs. *** per MT. Also, the landed value has decreased by *** US\$/MT since the POI of the last sunset review investigation.
 - xi. The non-injurious price of the domestic industry has also decreased.
 - xii. However, the decrease in landed price is higher than the decrease in the non-injurious price of the domestic industry. As a result, injury margin increased from *** % (USD *** per MT) to *** % (USD *** per MT), which is higher than the anti-dumping duty already in force, and is insufficient to counteract dumping. Thus, there is need to enhance the quantum of ADD in force.
 - xiii. The above facts constitute sufficient grounds for enhancement of quantum of duty as a result of changed circumstances.
 - xiv. If this scenario is allowed to remain, the performance of the domestic industry will be adversely affected.

F.2 Views of the Other Interested Parties

48. The various submissions made by the European Commission during the course of the present investigation with regard to miscellaneous submissions are as follows:

The Domestic Industry is trying to create a dominant market position and artificially exclude competition as there is already duty in force on the subject goods from EU and China and investigation against Russia is ongoing. Further, increase of duties on EU imports would only restrict the source of supply and consumer choice.

49. None of the exporters, importers, consumers and any other interested party has filed any comment or submissions with regard to scope of the present midterm review investigation.

F.3 Examination by the Authority

50. As regards the monopoly issue raised by some interested parties, the authority notes that purpose of anti-dumping duty is to ensure fair trade and provide a level-playing field to the domestic industry. It is neither a measure to restrict import nor to cause an unjustified increase in the selling price of the products. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to provide a level playing field to the domestic industry against the unfair trade practice of dumping adopted by the exporters from the subject country.
51. The issues raised by the domestic industry have been addressed elsewhere in this notification at appropriate places.

G. Assessment Of Dumping – Methodology and Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

G.1 Views of the Domestic Industry

52. The following are the submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation and considered relevant by the Authority:
- i. The domestic industry has not been able to get the information about cost and prices of subject goods prevailing in the subject country despite its best efforts. This information is not publicly available.
 - ii. The petitioner has determined Normal Value in EU on the basis of cost of production in India, considering the best utilisation norms of raw materials and utilities of the domestic industry
 - iii. The applicant has considered raw material price of Caustic Soda and Ammonia as per DGCI&S data regarding imports into India from the world and the domestic industry's price for Nitric Acid. The rates of power as prevailing in the subject country have been adopted. All other conversion cost is based on cost of the domestic industry, duly adjusted for selling, distribution and administrative expenses. Profit of 5% has also been added.
 - iv. Export price has been determined on the basis of the average import price from subject country and thereafter making due adjustments based on the best available information with the industry so as to make it comparable with normal value.
 - v. The dumping margin is not only more than de-minimis, but also significantly high. The same is higher by *** % as compared to the last sunset review investigation.
 - vi. As regards the argument that evidence regarding dumping does not support the contention that dumping from EU has increased and that the present duty does not remove the injury caused by the same, the petitioner submits that under the law, in order to ascertain increase in dumping, reference to volume of imports or dumping margin is considered. The import volume has increased significantly even after the existing anti-dumping duty in force.
 - vii. As regards dumping margin, while the petitioner has established increase in dumping margin, it is for the European Producers to show otherwise.

G.2 Views of the Other Interested Parties

53. The European Commission has submitted that the evidence produced by the domestic industry regarding dumping does not support the argument that dumping from EU has increased and that the present duty does not remove the injury caused by the same.

G.3 Examination by the Authority

54. According to Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, following can form the basis for determination of normal value in the exporting country:
- The price of the like article in the domestic market of the exporting country in the ordinary course of trade,
 - Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country,
 - The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.

G.3.1 Normal Value

55. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of EU for determining normal value in EU. The petitioner has claimed that they could not get any evidence regarding the actual selling price prevailing in the domestic market of the EU. None of the exporters in EU has cooperated with the Authority by submitting questionnaire response. The Authority notes that in the absence of response from any EU producer, the normal value cannot be determined on the basis of the actual selling price of like article in the domestic market of EU. The Authority has, therefore, constructed normal value by considering the estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so determined is *** US\$/MT

G.3.2 Export Price

56. None of the exporters from the subject country has provided any information/details of export price. The Authority has, therefore, determined the export price for producers/exporters of European Union on the basis of the DGCI&S import data. Further, the net export price at ex-factory level in respect of all exporters from European Union has been determined after making due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges on the basis of best available information . The net export price so determined is US\$ ***/ MT

G.3.3 Dumping Margin

57. On the basis of the normal value and export price so determined at ex-factory level; the dumping margin during the POI for all exporters/producers from the European Union determined is shown in the Dumping Margin Table below.

SN	Particular	Unit	POI
1	Exchange Rate	USD/INR	66.70
2	Normal Value	US\$/MT	***
3	Net Export Price	US\$/MT	***
4	Dumping Margin	US\$/MT	***
5	Dumping Margin	%	***
6	Dumping Margin	% Range	25 – 35

H. Methodology for Injury Assessment, Examination of Injury and Causal Link

H.1. Injury Determination

H.1.1 Views of the Domestic Industry

58. The following are the injury related submissions made by the domestic industry during the course of the present investigation :

59. The domestic industry had filed duly documented petition considering POI to be July, 2016 to June, 2017. However, the Authority initiated the investigation considering October, 2016 to September, 2017. Accordingly, the applicant filed the updated annexures which inter alia demonstrate the following :
- i. The imports from the subject country have substantially increased in absolute terms, despite anti-dumping duty being in force.
 - ii. The landed value has decreased over the injury period.
 - iii. Market share of the subject imports in total imports entering into India has also shown an increase.
 - iv. Imports are significantly undercutting the domestic prices despite current anti-dumping duties.
 - v. Landed price of imports is substantially below the non-injurious price of the domestic industry. The imports are, thus, resulting in significant price underselling in the market.
 - vi. Average Inventory of the domestic industry has increased from *** MT to *** MT.
 - vii. Despite the fact that the anti-dumping duty on the imports from the subject country has been in force for quite some time, the domestic industry has suffered continued material injury, thus establishing the need for continuation of anti-dumping duty at enhanced rate.
 - viii. The injury would be likely to continue in the event of revocation or reduction in the quantum of duties.
 - ix. The existing measure is not sufficient to counteract the dumping which is causing injury.
 - x. Despite existing anti-dumping duties, the product under consideration continues to be exported to India below its normal value resulting in dumping.
 - xi. The current duty is no longer sufficient to address the injury to the domestic industry; the non-injurious price of the domestic industry has substantially increased; and therefore the quantum of anti-dumping duty is required to be modified/enhanced,
 - xii. Since the present investigation is for review and modification of antidumping duty, the Designated Authority is required to consider whether the dumped imports are preventing the domestic industry from improving its performance to the level allowed in determination of NIP by the Authority. While the trends in some parameters may be positive, the domestic industry is still earning sub-optimal level of return on investment (“ROI”) and is almost stagnating itself which shows continued injurious effect of the present dumping. There are other factors which witnessed a negative trend. The import volume have increased significantly, price undercutting is positive and significant, the landed price has been declining since the extension of anti-dumping duty in 2014 except minor increase in the POI as compared to the preceding year. Resultantly, the injury margin has increased which is now more than the anti-dumping duty in force.
 - xiii. The applicant also referred to the EU regulation 3.5 which provides consideration of the fact of past dumping and the fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effects of dumping while assessing injury.
 - xiv. As regards argument of unit price of EU being higher than the other countries, the petitioner submits that the import price of the subject goods from EU is lesser than the import price from China and Russia. Price undercutting being positive and significant justifies the same.
 - xv. As regards the claims that there should be no increase in the current level of anti-dumping duty, the petitioner submits that currently the price underselling is higher than the anti-dumping duty in force which demonstrates the need for enhancement of quantum of the anti-dumping duty in force.
 - xvi. The European Commission has not highlighted the presence of any other factor which led to the injury to domestic industry. Injury to the domestic industry is solely on account of the dumped imports from the European Union.
 - xvii. The increase in capacity was undertaken keeping in view the increase in demand in India. The same is a sound business decision. The petitioner holds a capacity of *** MT as against established Indian demand of 70,800 MT in the POI.

H.1.2 Views of the Opposing Interested Parties

60. The opposing interested party made submissions as under :
- i. Capacity, capacity utilization, production, sales volumes and sales values and profits of the domestic industry all show increase.
 - ii. There is no negative effect on the price of domestic industry caused by the allegedly dumped EU imports as the unit price has always been higher than the price of both Chinese and Russian imports and also higher than the average unit price of all imports. This combined with the ability of the domestic industry to increase its selling price demonstrate absence of any negative effect.
 - iii. Keeping in perspective the positive economic indicators of the domestic industry, there should be no increase in the current level of anti-dumping duty.
 - iv. Injury, if any, is on account of other factors attributable to the domestic industry and not due to the dumped imports from the European Union.
 - v. The Domestic Industry made investments in 2015-2016 to increase their capacity when there was already enough, if not more, to satisfy the domestic demand.

H.1.3 Examination by the Authority

61. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices of the like article in the domestic market and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
62. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The issues raised by various interested parties have been dealt with in the relevant paragraphs of this notification.
63. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

64. For the purpose of assessing the state of injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped present imports of the subject goods from subject country on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between the dumping and injury, if any. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties. Accordingly the volume and price effects of dumped imports have been examined as follows.

A. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a) Assessment of Demand and Market Share

65. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed and presented in the Table given below shows increase over the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***
Captive Consumption of DI	MT	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject country- EU	MT	1,706	1,869	5,746	3,696
Import from country attracting ADD-China PR	MT	11,432	12,688	5,683	7,925
Import from country undergoing ADD Investigation- Russia	MT	-	192	4,034	4,152
Imports from Other Countries	MT	-	21	24	24
Total Demand/consumption including Captive	MT	55,265	62,772	63,763	68,515
Domestic Industry Sales	%	***	***	***	***
Captive Consumption of DI	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Subject country- EU	%	3.09	2.98	9.01	5.39
Import from country attracting ADD-China PR	%	20.69	20.21	8.91	11.57
Import from country undergoing ADD Investigation- Russia	%	-	0.31	6.33	6.06
Import from other Countries	%	-	0.03	0.04	0.04
Total Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00

66. The authority notes that:

- i. The demand for the product under consideration has shown an increase throughout the injury period.
- ii. Import from the subject country has increased throughout before registering decline in POI. There was significant jump in imports during 2016-17 (i.e. the year immediately preceding to the POI). The market share of the imports from subject country has gone up from 3.09% to 9.01% before declining to 5.39% in the POI.

b) Import Volumes and Market Share

67. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that with regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The information regarding imports and market share is provided in the table below:

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Imports from Subject country- EU	MT	1,706	1,869	5,746	3,696
Country attracting ADD-China PR	MT	11,432	12,688	5,683	7,925
On-going Investigation- Russia	MT	-	192	4,034	4,152
Imports from Other Countries	MT	-	21	24	24
Total Imports	MT	13,138	14,770	15,488	15,797
Imports in relation to					
Total Imports	%	12.98	12.65	37.10	23.40
Total Indian Production	%	3.29	3.16	9.68	5.76

68. The Authority notes from the above that the volume of imports from EU has increased to about 217% in the period of investigation as compared to the base year. Similarly, the share of imports from subject country in

total imports has increased from 12.98% in base year to 23.40% in POI after reaching a high of 37.10% in 2016-17. The volume of dumped imports from subject country witnessed an increase from 3.29% in the base year to 5.76% in the POI during the same period in relation to production in India.

B. Price Effect

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules states as under:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

70. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price Undercutting

71. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.
72. It would be seen that the price undercutting from the subject country is positive in 2015-16 and POI.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Landed price of imports	Rs/MT	39,876	39,192	35,743	36,819
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
	Rs/MT	(***)	(***)	***	***
Price Undercutting	Range %	(5-10)	(0-5)	5-10	5-10

b. Price Suppression and Depression

73. In order to assess as to whether imports from subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry over the injury period along with the landed price of imports over the injury period, and shown in the table below:

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	96	101
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	102	108
Landed value	Rs/MT	39,876	39,192	35,743	36,819

Trend	Indexed	100	98	90	92
-------	---------	-----	----	----	----

74. The Authority notes that the landed price of imports is below the level of cost of production and selling price of the domestic industry for the product concerned during POI. The price depression and suppression effect though are not visible.

c. **Price Underselling**

75. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The analysis shows that during the period of investigation, the landed price of subject imports were below the non-injurious price of the domestic industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particulars	Unit	POI*(INR)	POI* (USD)
Landed Price	Per MT	36,819	552.01
Non-Injurious Price (NIP)	Per MT	***	***
Price underselling	Per MT	***	***
Price underselling	%	***	***
Price underselling	Range	0-5	0-5

* Oct'16-Sep'17

76. The Authority notes that the dumped imports from subject country are coming to India at prices below the non-Injurious price/fair price of the domestic industry, thus resulting in positive price underselling.

c. **Economic Parameters of the Domestic Industry**

77. As per Annexure II to the AD Rules, the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of the imports of subject goods on domestic producer(s) of the subject goods. The relevant extract of the said Rule is reproduced herein below-

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

78. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a) **Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

79. The volume of domestic production and effects of dumped imports on the domestic operation of the domestic industry have been examined in terms of total production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry. Capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry have been as under:-

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	111	111
Production- Sodium Nitrite	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	122	129

Production-Plant (SNI+SNA)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	118	126
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	107	114
Sales Domestic	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	122	130

80. From the data in the table above, the Authority notes that:

- i. The domestic industry has enhanced its capacity in 2015-16 and since then the capacity has remained at the same level. The production of the product concerned has increased throughout the injury period.
- ii. The capacity utilization of the domestic industry has also increased throughout the injury period.
- iii. The domestic sales of the domestic industry have also increased over the injury period.

b) Profitability, Return on Investment and Cash Flow

81. The return on investment, profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit during the injury period is as indicated in the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	98	96	101
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	104	102	108
Profit/ Loss	Rs/MT	(***)	***	***	***
Indexed	Indexed	-100	237	233	282
Profit/ Loss	Rs.Lacs	(***)	***	***	***
Indexed	Indexed	-100	289	283	366
Profit before Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	671	608	814
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	782	816	941
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	608	516	636

82. From the examination of the data in the table above the Authority notes that the domestic industry has come out from the situation of financial losses and has been earning profits. Consequently, profit before Interest, cash profits and return on investment have shown increase.

c) Market Share in Demand

83. Market share of the domestic industry in demand for the product under consideration is given in the table below:

Particular	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Market Share in Demand including Captive					
Domestic Industry Sales	%	***	***	***	***
Captive Consumption of DI	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Subject country- EU	%	3.09	2.98	9.01	5.39
Country attracting ADD-China PR	%	20.69	20.21	8.91	11.57
Country undergoing ADD investigation - Russia	%	-	0.31	6.33	6.06
Other Countries	%	-	0.03	0.04	0.04
Total Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00

84. It is noted from the above table that while the market share of domestic industry has marginally increased after the base year and has thereafter remained more or less same, the share of imports from European Union has increased from 3.09% in base year to 5.39% in POI, rising to a high of 9.01% in 2016-17

d) Employment, productivity and wages

85. The analysis of the number of employees employed by the domestic industry, its productivity and wages paid show as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	101	101
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	135	137
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	121	128
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	122	129

86. The Authority notes that:

- (a) The employment with the domestic industry has remained more or less same over the injury period.
- (b) The wages have increased throughout the injury period.
- (c) Productivity per employee and per day has improved throughout the injury period.

e) Inventories

87. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	198	217	385

88. Average inventories with the domestic industry increased throughout the injury period.

f) Growth

89. The Authority notes from the data given in the Table below that the growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales, selling price, profitability and return on investment has increased in POI as compared to 2015-16.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI*
Growth (year to year)					
Production	%	-	***	***	***
Domestic Sales	%	-	***	***	***
Cost of Sales	%	-	(***)	(***)	***
Selling Price	%	-	***	(***)	***
Profit/ Loss per unit	%	-	***	***	(***)
Return on investment	%	-	***	(***)	***

g) Ability to Raise Capital Investments

90. The domestic industry has claimed that their ability to raise capital investment will be adversely impacted if the injury suffered by the domestic industry remains unaddressed.

h) Factors affecting domestic prices

91. The Authority notes that prices of imported material is below the net sales realization and also below the non-injurious price of the domestic industry, causing price undercutting and price underselling in the Indian market. However, import from the subject country does not seem to have affected domestic price since the net sales realization by the domestic industry is more than the non-injurious price of the domestic industry.

i) Magnitude of dumping margin

92. The Authority notes that the dumping margin determined against the subject country is not only more than de-minimis but also significant despite anti-dumping duty being in force.

SN	Particular	Unit	POI
1	Exchange Rate	USD/INR	66.70
2	Normal Value	US\$/MT	***
3	Net Export Price	US\$/MT	***
4	Dumping Margin	US\$/MT	***
5	Dumping Margin	%	***
6	Dumping Margin	% Range	25 – 35

Magnitude of Injury and Injury Margin

93. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed values

of the subject imports from the subject territory to determine injury margin. The injury margin has thus been worked out as follows:

Particular	Unit	Oct'16- Sep'17 *
Non-Injurious Price (NIP)	US\$/MT	***
Landed Price	US\$/MT	552.01
Injury Margin	US\$/MT	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin	% Range	0-5

I. Conclusion on injury

94. Considering various parameters relating to material injury provided under the Anti-Dumping Rules, the Authority concludes as follows
- i. The import of subject goods from the subject country at dumped prices has increased throughout before registering decline in POI. There was significant jump in imports during 2016-17 (i.e. the year immediately preceding to the POI). The market share of the imports from subject country has gone up from 3.09% to 9.01% before declining to 5.39% in the POI.
 - ii. Price undercutting is positive and dumping margin as well as injury margin have also increased.
 - iii. The import from the subject country however has not impacted the domestic industry adversely in terms of price parameters since their net sales realization is more than the non-injurious price of the domestic industry.
 - iv. The performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, market share, capacity, profit, cash profit and return on capital employed.
 - v. Despite the landed price of imports being below the level of cost of production of the domestic industry these imports have not caused price depression and/or suppression.

I. Causal Link and other factors

95. Annexure-II to the Rules provides as follows with regard to Causal Link:

"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the Designated Authority. The Designated Authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, interalia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."

96. The Authority examined whether other factors listed under the Rules caused injury to the domestic industry.

Volume and value of imports not sold at dumping prices:

97. The imports from China are also attracting anti-dumping duty. The domestic industry has already filed a petition seeking imposition of anti-dumping duty on imports from Russia. The Authority is separately investigating the matter. Imports from other countries are not significant in volume and hence cannot be considered as the cause of the injury claimed to be suffered by the domestic industry.

Contraction in demand or Changes in the pattern of consumption:

98. Demand for the product under consideration has not registered any negative growth. Instead, it has increased

and shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a factor contributing to the injury to the domestic industry. Moreover, the pattern of consumption with regard to the product under consideration has also not undergone any change. Change in the pattern of consumption is thus not a factor that could have contributed to the injury claimed by the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

99. There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury claimed by the domestic industry.

Developments in technology:

100. Technology for production of the product has not undergone any change nor is any change likely in the foreseeable future. Developments in technology is therefore, not a factor of injury claimed by the domestic industry.

Export performance:

101. The petitioner exports the product under consideration. The export volume has increased only over the injury period and therefore it could not be the factor responsible for injury claimed by the domestic industry.

Productivity of the domestic industry

102. Productivity per day as well as productivity per employee has improved consistently over the injury period and therefore could not be the cause of injury claimed by the domestic industry.

Any Other factors

103. The capacity expansion from *** MT to *** MT undertaken by the domestic industry during 2015-16 is one of the factors responsible for higher injury margin as compared to the one in the last sunset review investigation.
104. The essential facts of the investigation gathered by the Designated Authority during the course of the investigations and analyzed by the Authority in the present disclosure statement was disclosed to the interested parties in order to enable these interested parties to offer their comments on these facts.

K. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

105. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

Submissions made by the Domestic Industry

106. The following comments on Disclosure statement are submitted by domestic industry:
- The scope of the present investigation is limited only to re-determination of dumping margin and injury margin as it is midterm review investigation.
 - Extending the scope of the present investigation to a complete analysis of injury as if it was a petition for fresh imposition of ADD and assessment of whether or not the domestic industry has suffered material injury is without any legal and factual basis.
 - The normal value has been calculated by the Authority considering normated cost of the domestic industry, which is inconsistent with the law. The Authority is required to adopt actual cost of production and not normated cost of production. Without prejudice, the NIP itself is understated thus leading to understated normal value. The resultant dumping margin proposed by the Authority is significant low.
 - The non-injurious price determined is too low. The NIP has been inappropriately reduced by modifying apportionment methodology and excluding a number of elements of expenses. It would be inappropriate to change the methodology that was fixed at the time of original investigation. The Designated Authority has earlier conducted investigations in the matter of Sodium Nitrite from China and Europe and has determined NIP.

- v. The imports from the subject country have substantially increased in absolute terms and the market share of the subject imports in total imports entering India has also shown an increase.
- vi. Dumping margin, price undercutting and injury margin have increased as compared to the last SSR investigation.
- vii. The price undercutting has become 9.55% from -3.13% which was in the POI of the last sunset review investigation. The landed price of imports is below the level of cost of production and selling price of the product concerned during POI. Landed value has decreased by 97.71 US\$/MT since the POI of the last sunset review investigation.
- viii. The NIP of the domestic industry has also decreased. However, the decrease in landed price is higher than the decrease in the non-injurious price of the domestic industry. The imports are, thus, resulting in significant price underselling in the market.
- ix. Injury margin has increased and it is higher than the anti-dumping duty already in force. Thus, the injury margin has undergone a considerable change to the extent of undermining the remedial effects of anti-dumping duty imposed.
- x. The petitioner compared the conclusions drawn between the present MTR investigation and the last China SSR investigation dated 19th July 2017 vide Notification No. 15/06/2016/DGAD. It would be seen that with the same set of facts, the conclusions drawn by the authority are totally different.
- xi. There are certain parameters in respect of which the injury is more prominent in the present MTR investigation as compared to the SSR investigation. Imports are continuously increasing, as against decline in imports in the SSR investigation. In the SSR investigation the selling price had continued to increase with increase in costs. However, the Authority upon reviewing the overall performance of the domestic industry concluded continued dumping and continued injury.
- xii. The Authority has not even examined likelihood parameter while undertaking injury analysis. While the Authority has examined likelihood in all past MTR investigations in the injury analysis, petitioner has not understood the reason for ignoring the same in the present case.
- xiii. Likelihood of intensified dumping and consequent injury is imminent as volume of imports has remained significant since inception and even in the present investigation. European producers have significant surplus capacities and the percentage of exports in total turnover of PUC in the subject country is massively high. If these ADD are not enhanced, the imports shall have significant suppressing and/or depressing effect on the prices of the domestic industry.
- xiv. The imports are significantly undercutting the domestic prices even when the anti-dumping duty is in force. It is likely that due to price attractiveness of Indian market; the same will continue and will force the Domestic Industry to reduce its prices further if the anti-dumping duty is allowed to be continued without any enhancement in its quantum.
- xv. Regarding the concern of the Authority that the performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, market share, capacity, profit, cash profit and return on capital employed and that the Net sales realization is more than the Non-Injurious price of the domestic industry; it is submitted that since the present petition is for review and modification of antidumping duty, the Authority is required to assess whether the dumped imports are preventing the domestic industry from improving its performance to optimum levels.
- xvi. As regard the argument on capacity expansion during 2015-16, it is submitted that increase in capacity was taking into consideration the increase in demand in India. Further, present investigation being a review investigation, the causal link is not required to be seen. Further, per unit cost structure of the domestic industry has not increased in a manner so as to show that the capacity expansion undertaken by the domestic industry is responsible for the claimed injury.
- xvii. The Authority seems to have proceeded on a premise that the sole cause of the injury to the domestic industry must be dumped imports and seems to overlook the legal requirements that dumping need be only one of the causes of injury to the domestic industry.

- xviii. The circumstances prevailing during the previous sunset review have undergone a major change justifying the need for enhancement of quantum of current anti-dumping duty in force.

Submissions made by Other Interested Parties

107. The following comments on Disclosure statement are submitted by other interested parties:

- i. As assessed by the Authority, imports from the EU have increased in volume until 2016-17, but then they registered a significant decline (****) in the POI, together with a decline in market share.
- ii. As regards the effect of EU imports on domestic prices, while it seems that the undercutting margin became positive in 2015-16 and the POI (although it is rather low), the Authority has found that EU imports didn't cause any price depression nor price suppression to the domestic industry. In fact, the domestic industry was even able to increase its selling price, thus invalidating the claim that the low price of EU imports has forced them to reduce their domestic price.
- iii. As confirmed by the Authority, capacity, capacity utilisation, production and domestic sales of the domestic industry have increased during the period considered.
- iv. Likewise, profitability turned positive and increased significantly. In particular, the Authority notes that "the domestic industry has come out from the situation of financial losses and has been earning profits. Consequently, profit before interest, cash profits and return on investment have shown increase".
- v. As regards market share, the market share of domestic industry has increased and has remained stable since then.
- vi. Employment didn't decrease either. On the contrary, wages have increased, showing that EU imports have no negative effect on the domestic job market.
- vii. From the parameters and trends summarised above, it is clear that the existing AD duties have proved effective in remedying the injury caused by dumped imports by lifting the domestic industry from a past situation of financial losses to the present profitable condition.
- viii. As rightly underlined by the Authority, injury to the domestic industry, if any, can be attributed to the capacity expansion it undertook in 2015-16.
- ix. It is submitted that the European Commission had already raised the point about the need to separate the injury, if any, attributable to dumped imports from that which is caused by other factors, as provided for in Art. 3.5 of the WTO ADA.
- x. The European Commission considers that there is no element that would justify an increase in the current level of AD duties, which have proved effective in removing the injury to the domestic industry, as shown by its improved performance.
- xi. Increasing the current duty level under these circumstances would therefore be in breach of Article 11.1 of the WTO ADA.
- xii. The European Commission trusts that the Indian authorities will terminate the present mid-term investigation without any change in the level of AD duty already in force on EU imports.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

108. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
- i. The Authority notes that the methodology adopted for NIP determination in this investigation is the same as the one adopted consistently in previous investigations. It is noted that in the manufacture of PUC, significant proportion of costs consists of cost of raw material costs and utilities, which have been allowed on actuals as claimed by the DI. It may be added that the DI has number of products under anti-dumping investigation for last several years. It was noticed during the anti-dumping investigation on imports of Sodium Nitrite ,

originating in or exported from European Union vide notification No. 15/1009/2012-DGAD dated 12.05.2014 that the company had adopted different methods of allocation for two different joint products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. Since, the domestic industry had not adopted the consistent method as required under Annexure-III of AD Rules, a uniform methodology has been applied for allocation of others costs since then in respect of both products namely Sodium Nitrate and Sodium Nitrite. There has been no change in methodology thereafter.

- ii. In regard to comparison of two different investigations by the domestic industry, it is noted that the objective of the Authority is to ensure fairness and justice to all the interested parties.

L. CONCLUSION

109. After examining the submissions and contentions of interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal value. Even injury margin is higher as compared to the anti-dumping duty in force. The increase in the injury margin however is partly attributable to the capacity expansion undertaken during 2015-16.
- b) The market share of the imports from subject country has increased in the POI as compared to the base year of the injury period. The import from the subject country however has not impacted the domestic industry adversely in terms of price parameters since their net sales realization is more than the non-injurious price of the domestic industry
- c) There is overall improvement in the health of the domestic industry. Its production, sales, market share, profit and return on capital employed have registered consistent growth.

M. RECOMMENDATION

110. Taking a holistic view of the conclusion drawn above, the Authority does not recommend enhancement of anti-dumping duty. The authority however recommends continuation of anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 37 /2014-Customs (ADD) dated 08.08.2014 on imports of subject goods from the subject country.

N. FURTHER PROCEDURE

111. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Dir. Genl.